

सूबे के पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी हैवेल्स इंडिया 50 एकड़ भूमि पर 800 करोड़ का करेगी निवेश

लखनऊ। प्रदेश को दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश जल्द देश का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र (योडा) में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण को मंजूरी दी है। क्लस्टर में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 50 एकड़ में 800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और घरेलू उपकरणों का निर्माण करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण से प्रदेश न सिर्फ देश का तकनीकी शक्ति केंद्र बनेगा, बल्कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के तहत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाएंगे ताकि विदेशों में निर्यात को और बढ़ावा दिया जा सके।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 10 में बनने वाले क्लस्टर को 539 करोड़ रुपये की लागत से 206 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 144.48 करोड़ रुपये की मदद देगी और शेष 393.90 करोड़ रुपए योडा की ओर से खर्च किया जाएगा। इसकी शुरुआत एक जुलाई से होगी और तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

सिर्फ फैक्टरी एसिया नहीं, बल्कि एक पूरी तकनीकी दुनिया होगी

सीएम योगी की संकत्यना के अनुरूप प्रदेश में बढ़ते निवेश को देखते हुए वैश्विक स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक फैक्टरी एसिया नहीं, बल्कि एक पूरी तकनीकी दुनिया होगी, जहां पहले से तैयार फैक्टरी, मीटिंग कक्ष, छात्रावास, बिजनेस सेंटर और स्किल ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां काम करने वालों को काम के साथ-साथ रहने और सीखने की पूरी सुविधा मिलेगी।

- आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश



539 करोड़ लागत से 206 एकड़ में विकसित होगा क्लस्टर, ग्रेटर नोएडा में एक जुलाई से शुरू होगी परियोजना

क्लस्टर में ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम और हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके अलावा 176 रेडी-टू-यूज आरसीसी फैक्ट्री शेइंस की सुविधा होगी। दो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिनमें कुल 176 यूनिट्स होंगी ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को तुरंत निर्माण कार्य शुरू करने की सुविधा मिले सके।

युवाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़ी ट्रेनिंग देगा। परियोजना परिसर में कन्वेशन सेंटर और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ईएमसी में बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और किराए के ऑफिस के लिए कामर्शियल बिल्डिंग और एक कन्वेशन सेंटर प्रस्तावित है।

